भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2175
सोमवार, 05 अगस्त, 2024/14 श्रावण, 1946 (शक)

देश में बेरोजगार युवा

2175. डॉ. बायरेड्डी शबरी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में बेरोजगार युवाओं की अनुमानित संख्या के बारे में आंकड़े हैं और यदि हां, तो विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के नांदयाल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा देश में युवाओं में बेरोजगारी दर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि आज बड़ी संख्या में लोग कृषि से सेवा क्षेत्र की ओर जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नांदयाल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से काम के लिए देश के अन्य क्षेत्रों में जाने वाले मजदूरों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (ङ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2022-23 के दौरान क्रमशः 10.0% थी। पीएलएफएस रिपोर्ट बेरोजगारी दर (यूआर) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और अखिल भारत आधार पर जारी करती है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि अलग-अलग रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि, जो पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार सृजन को बढ़ावा देना चाहती है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और अवसरों की प्रधान मंत्री पैकेज की घोषणा की है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कृषि क्षेत्र में सामान्य स्थिति में कामगारों का प्रतिशत वितरण 2022-23 में 45.8% था।

इसके अलावा, नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति पर 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में नंदयाल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित आंध्र प्रदेश राज्य और देश दोनों में नीचे दी गई तालिका के अनुसार वृद्धि की प्रवृत्ति है:

(%)

वर्ष	आंध्र प्रदेश	**अखिल भारत**
2018-19	45.0	38.1
2019-20	47.4	40.9
2020-21	47.5	41.1
2021-22	47.9	42.0
2022-23	48.2	44.5

स्रोत: पीएलएफएस

उपरोक्त तालिका के आंकड़े दर्शाते है कि आन्ध्र प्रदेश और देश में अधिक युवा श्रम बल में शामिल हो रहे हैं।

*****